

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 1390]** No. 1390] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016 ∕ज्येष्ठ 13, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/JYAISTHA 13, 1938

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2016

का.आ.1987(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप—धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2033(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, जो भारत के राजपत्र तारीख 11 अगस्त, 2014, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में काटापूकूर (पश्चिम बंगाल) से बीलपूर (पश्चिम बंगाल) तक परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 21 जनवरी, .2016, तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है. उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए :

और, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरादायी होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

2840 GI/2016 (1)

### अनुसूची

पुलिस स्टेशन : खण्डघोष		जिला : वर्द्धवान	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (आर. एस.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	माषीशा—57	448	00	05	70
		449	00	03	90
		1255	00	02	90
		452	00	01	20
2	नपाड़ा—56	1535	00	02	90
		1536	00	20	70

[फा. सं. आर.-25011/14/2014-ओ.आर-I]

पवन कुमार, अवर सचिव

#### MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2016

**S.O. 1987(E).**—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2033(E) dated 7th August, 2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 11th August, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying for the transportation of crude oil from Kantapukur (West Bengal) to Bolpur (West Bengal) by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 21.01.2016;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government of India;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Cental Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P& MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

### **SCHEDULE**

P S: Khandoghosh		strict : Burdwan	State: West Bengal			
Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No. (R.S.)	Area			
			Hectare	Are	Square meter	
1	2	3	4	5	6	
1	Mashila-57	448	00	05	70	
		449	00	03	90	
		1225	00	02	90	
		452	00	01	20	
2	Napara-56	1535	00	02	90	
		1536	00	20	70	

[F. No. R-25011/14/2014-OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.